>

Title: Need to review the decision of ban on export of cotton by the Government.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं देश के कपास उत्पादन करने वाले किसानों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। यह समस्या सरकार द्वारा निर्मित है। देश में कपास की उपज देश की जरूरत से अधिक हो रही है। पिछले वर्ष भी हमारे देश में अधिक उपज हुई थी और हम कपास का निर्यात कर रहे थे। इस वर्ष भी कपास निर्यात करने की देश की पालिसी होते हुए भी अचानक छह मार्च को वाणिज्य मंत्री ने कपास निर्यात पर पाबंदी लगाने से कपास के दाम एक हजार रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था जब कपास का मूल्य छह हजार रुपए प्रति क्विंटल था, तो अचानक वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, तो कपास का मूल्य तीन हजार रुपए मतलब आधा दाम हो गया था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बार-बार ऐसे निर्णय लेने के कारण किसान परेशान है और कपास उत्पादन करने वाले किसानों का नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में दो सौ से ढाई सौ बेल्स की कपास की गठानों की जरूरत है, जबकि हमारे यहां वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में अधिक उपज हुई है और उपज लगातार बढ़ती जा रही है। बंगलादेश, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में, चाइना में भी भारतीय कपास की मांग हो रही है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है, यह नुकसान वाणिज्य मंत्रालय की वजह से हुआ है। कृषि मंत्री कहते हैं कि मुझसे पूछा नहीं गया है। कृषि मंत्री जी के बयान से शंका पैदा होती है। अखबारों में छप रहा है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दूसरी इंडस्ट्रीज से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए करोड़ों किसानों का नुकसान करने वाले वाणिज्य मंत्रालय की नीति पर हमें आरोप लगाना है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। किसानों का बार-बार नुकसान किया जा रहा है। ये किसान वहीं के हैं, जहां किसान आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं।